मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विकास ने बसाने का खाका खींचा

यूपी में 114 टाउनशिप बनेंगी

तैयारी

■ शैलेंद्र श्रीवास्तव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लोगों की आवासीय जरूरतें पूरी करने के लिए 114 टाउनशिप बसाने का खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 टाउनशिप बसाने का लक्ष्य दिया था। इस क्रम में आवास विभाग शहरवार 114 नई टाउनशिप बसाने जा रहा है, जिससे लोगों की आवासीय जरूरतें पूरी हो सकें। बताया जा रहा है कि नई टाउनशिप में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। बिजली के तार भूमिगत किए जाएंगे। पार्क के साथ पाथवे भी बनाए जाएंगे।

आबादी के हिसाब से टाउनशिप: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में तेजी से आबादी बढ़ रही है। इसके चलते शहर के आसपास के गांवों में प्रॉपर्टी डीलर अवैध रूप से प्लाटिंग कर कॉलोनियां बसा रहे हैं। शहरों के विकास का स्वरूप इससे बिगड़ रहा है। आए दिन प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के स्तर पर विधिक कार्रवाई के चलते विवाद सामने आते रहे हैं।

टाउनशिप में भूमिगत होंगे बिजली तार, पार्क- पाथवे भी बनेंगे

34 टाउनशिप में निर्माण योजनाओं की स्थिति

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 34 टाउनशिप का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया या तो चल रही है या फिर पूरी हो चुकी है। विकास प्राधिकरण आपसी समझौते से पूलिंग पर भूमि ले रहे हैं। इसके अलावा सीधे किसानों से समझौते पर भी भूमि ली जा रही है। पूलिंग पर भूमि देने वालों को विकास प्राधिकरण योजनाओं विकसित भूमि में फ्लाट देंगे।

बरेली, अयोध्या, आगरा, मेरठ, खुर्जा, रामपुर में योजना लांच हो चुकी है। गोरखपुर, चित्रकूट, बुलंदशहर, झांसी, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, लखनऊ आईटी सिटी, बांदा, गाजियाबाद, हापुड़-पिलखुआ में योजना लांच करने की तैयारी है। आवास विकास द्वारा प्रदेश के 10 से 15 शहरों में योजना लाने की तैयारी है।

होटल और अस्पताल के लिए जमीन आरक्षित

यूपी में कुछ सालों में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए बड़े होटले के लिए भूमि आरक्षित की गई है। प्रदेश भर में 43 भूखंड अब तक आरक्षित किए गए हैं। नर्सिंग होम, अस्पताल खोलने के लिए भी 107 भूखंड आरक्षित किए गए हैं। प्राधिकरण, आवास विकास परिषद को निर्देश दिया गया है कि वे योजनावार इसके लिए और भूखंडों को आरक्षित कर सकते हैं। इससे आवासीय योजनाओं का खर्च कम किया जा सकता है। व्यावसायिक भूखंडों को नीलामी पर बेंच कर अच्छी कीमत ली जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में 100 नई टाउनशिप बसाने का निर्देश आवास विभाग को दिया था। इसके आधार पर शहरों में टाउनशिप बसाने के लिए विकास प्राधिकरणों से प्रस्ताव मांगे गए थे। आवास विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेशभर के विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा 114 टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव दिया गया है। शहरों में आबादी के हिसाब से टाउनशिप का प्रस्ताव है।

15
शहरों में आवास विकास योजना लाने की तैयारी में

100
टाउनशिप बसाने का मुख्यमंत्री ने दिया था लक्ष्य

जी राम जी पर खर्च होगा करीब 40 प्रतिशत बजट

नई दिल्ली। मनरेगा की जगह लेने वाली विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (वीबी-जी राम जी) को इस साल ग्रामीण विकास विभाग को जारी कुल बजट में सबसे अधिक हिस्सा मिला है। विभाग के बजट का 40 प्रतिशत इसके लिए तय है। 'पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च' की ओर से जारी रिपोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग को जारी बजट का विश्लेषण है। राम जी के लिए बजट में 95,692 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

▶ ब्योरा P11